भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-117

उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य

117. **श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत निर्धारित सार्वभौमिक पहुंच, लैंगिक समानता, समावेशी शिक्षा, डिजिटल पहुंच, व्यवसायिक शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण जैसे घोषित उद्देश्यों के बावजूद इन प्रयासों का प्रभाव जमीनी स्तर पर अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत अब तक सीखने के परिणामों, संक्रमण दर तथा शिक्षा की गुणवत्ता में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रौद्योगिकी उपयोग को बढ़ावा देने, संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा प्रभावी अभिसरण एवं निगरानी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक संसाधन या प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं; और

(ङ.) यदि हाँ, तो सरकार ने अब तक इन मुद्दों के समाधान हेतु क्या कदम उठाए हैं और उनके क्या परिणाम रहे?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना-समग्र शिक्षा कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और एक समान एवं समावेशी कक्षा परिवेश की प्राप्ति हो। इस योजना के तहत, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर विभिन्न पहलों यथा अवसंरचना और संसाधनों तक पहुँच, अनुकूल

प्रतिधारण वातावरण बनाना, गुणवत्ता और नवाचार, अधिगम परिणाम और उनका मूल्यांकन, सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना, समावेशी और कौशल-आधारित पहलें, शिक्षकों की क्षमता-वृद्धि, तथा अध्यापक शिक्षा संस्थानों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

इसके परिणामस्वरूप, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसका प्रमाण सकल पहुँच अनुपात (जीएआर), जेंडर समानता सूचकांक (जीपीआई) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के नामांकन जैसे प्रमुख संकेतकों से मिलता है-

स्तर	जीएआर^		जीईआर का जीपीआई*		सीडब्ल्यूएसएन नामांकन*	
	2018-19	2024-25	2018-19	2024-25	2018-19	2024-25
प्राथमिक	97.15	97.83	1.0	1.0	1138326	943512
उच्च प्राथमिक	96.49	96.57	1.0	1.0	646735	698544
माध्यमिक	88.24	95.35	1.0	1.0	247788	324941
उच्चतर माध्यमिक	65.05	94.97	1.03	1.1	78648	149022

^स्रोत: एडब्ल्यूपीएंडबी, *स्रोत: संबंधित वर्षों का यूडाइज़

कक्षा 3, 5, 8 और 10 के विद्यार्थियों के भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अधिगम स्तर का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) का आयोजन वर्ष 2017 में और वर्ष 2021 में पुनः किया गया था। राज्य-वार और ज़िले-वार रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं और https://nas.gov.in/report-card पर उपलब्ध हैं।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, दिनांक 4 दिसंबर, 2024 को किया गया था ताकि कक्षा 3, 6 और 9 में बुनियादी, प्रिपरेटरी और मिडिल स्तर के अंत में विद्यार्थियों के बीच बेसलाइन प्रदर्शन को समझा जा सके। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की रिपोर्ट https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर उपलब्ध हैं। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के निष्कर्षों में एनएएस 21 के स्कोर की तुलना में बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान कौशल के संबंध में उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित होता है, जिससे एनईपी 2020 के तहत शुरू किए गए निपुण भारत मिशन का सकारात्मक प्रभाव दिखता है।

माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक की परिवर्तन दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो वर्ष 2018-19 में 68.8 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 75.1 हो गई है।

राज्य विशिष्ट प्रस्तावों के अनुसार शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों, विषय अध्यापकों, विशेषज्ञ व्यक्तियों, मास्टर प्रशिक्षकों, शिक्षा प्रशासकों, अध्यापक शिक्षकों, प्रमुख विशेषज्ञ व्यक्तियों के सेवारत प्रशिक्षण, नोडल एजेंसी के रूप में एससीईआरटी और डाइट के माध्यम से प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों के शिक्षकों सहित नव नियुक्त शिक्षकों, के प्रवेशकालिक प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

"एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार" के लिए स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) एक क्षमता वृद्धि कार्यक्रम है। अक्टूबर, 2020 में दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके निष्ठा ऑनलाइन का शुभारंभ किया गया था। वर्ष 2021-22 में माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए निष्ठा प्रशिक्षण का विस्तार किया गया है। निष्ठा के माध्यम से मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान एवं बाल्यकाल पूर्व देखभाल तथा शिक्षा (ईसीसीई) संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से सभी कार्यात्मक 613 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट्स) को केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तहत चरणबद्ध तरीके से उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर सरकार ने अब तक 246 डाइट्स के उन्नयन हेतु 2,429.59 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता संस्वीकृत की है।

इसके अतिरिक्त, एनईपी, 2020 की सिफारिशों के अनुरूप, सरकार ने अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) के संबंध में एक मार्गदर्शन प्रदान करने वाला दस्तावेज़ और राष्ट्रीय परामर्शदाता मिशन (एनएमएम).के संबंध में ब्लूबुक जारी की है। एनपीएसटी अलग-अलग चरणों/स्तरों पर शिक्षकों की क्षमताओं को परिभाषित करता है। एनएमएम संबंधी ब्लूबुक में स्कूल शिक्षकों की क्षमता वृद्धि हेतु उन्हें परामर्श प्रदान करने से संबंध में अलग-अलग तरीके बताए गए हैं।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) को अधिसूचित किया गया है, जोकि शिक्षा के साथ-साथ कला, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा इत्यादि जैसे विशिष्ट विषयों में 4 वर्ष की प्रमुख एकीकृत दोहरी स्नातक डिग्री है। इसका उद्देश्य उत्साही, अभिप्रेरित, योग्य, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित और कुशल शिक्षकों को तैयार करना है। आईटीईपी हेतु प्रवेश प्रक्रिया पिछली बार दिनांक 29 अप्रैल, 2025 को आयोजित राष्ट्रीय कॉमन प्रवेश परीक्षा (एनसीईटी) के माध्यम से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा संपादित की गई है।

*****